

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या: डी.ई.-25 (13)/203 / वि.कार्य / 2017-18 / 1590-1591 दिनांक:- 06/08/2018

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054

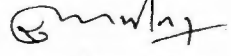
विषय:- विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 06 दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार


उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (150 प्रतियाँ) Delhi

DDE (PGMS)
Dir. of Education

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

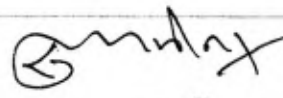
अतारांकित प्रश्न संख्या :- 06

दिनांक :- 06.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री विजेन्द्र गुप्ता

क्या उप मुख्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

प्रश्न	उत्तर																
(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की ओर से जारी तमाम आदेशों के बावजूद निजी स्कूल ईडब्ल्यूएस कोटे की स्थिति साझा नहीं कर रहे हैं.	जी नहीं, यह सत्य नहीं है।																
(ख) यदि हा तो सरकार इन स्कूलों के विरुद्ध क्या कार्रवाई कर रही है.	लागू नहीं होता।																
(ग) क्या यह भी सत्य है कि इन स्कूलों द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अनेक बच्चों को किसी-न-किसी कारण प्रवेश नहीं दिया जाता तथा सरकार की लचीली नीति का फायदा उठाकर जरूरत मन्दों को प्रवेश न देकर पैसे लेकर खाली सीटों को सामान्य श्रेणी के बच्चों को प्रवेश दे दिया जाता है? इस पर विस्तार से स्थिति स्पष्ट करें.	यह सत्य नहीं है। ऐसा कोई मामला सज्जान में नहीं आया है कि पैसे लेकर सामान्य श्रेणी के बच्चों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी में प्रवेश दिया गया हो। जहाँ स्कूल प्रबंधन के द्वारा किसी जरूरतमंद बच्चे के प्रवेश में कोई कठिनाई पैदा की जाती है वहाँ संबंधित जिला के उप शिक्षा निदेशक कार्यालय द्वारा दाखिला सुनिश्चित कराया जाता है। इस संदर्भ में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यूपीसी न 3358/2013 में जारी फैसले दिनांक 03/09/2013 के अनुसार सामान्य श्रेणी के अनुपात में दाखिले न होने पर निजी स्कूल, ईडब्ल्यूएस / डी जी श्रेणी के बच्चों को "इन वेटिंग" श्रेणी में रख देते हैं। इस स्थिति पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी आदेशानुसार शिक्षा निदेशालय ने दिनांक 25/04/2018 और 24/07/2018 को ज्ञापन जारी किये हैं तथा "इन वेटिंग" आवेदकों को भी प्रवेश मिल जाये, विभाग द्वारा इस बात का भी ध्यान रखा जाता है।																
(घ) चालू शिक्षा सत्र में अब तक कितनी सीटें ईडब्ल्यूएस कोटे से भरी गई हैं और कितनी खाली हैं.	सत्र 2018-19 में कुल 43882 सीटों के लिये झा किया गया था और अभी तक कुल 31526 सीटें भरी गई हैं, लगभग 9064 मामलों में स्कूलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार आवंटित सीटों के लिये संबंधित अभिभावकों ने दाखिले हेतु आवंटित स्कूलों से संपर्क ही नहीं किया है। बाकी बची सीटों में दाखिले की प्रक्रिया अभी भी जारी है।																
(ङ) जरूरत मन्द बच्चे इस योजना का फायदा उठा सके, सरकार इस पर क्या कार्रवाई कर रही है.	इस योजना का लाभ सभी योग्य आवेदक उठा सके इसके लिये प्रवेश प्रक्रिया के दौरान काफी प्रचार किया जाता है ताकि इसकी जानकारी अधिक से अधिक अभिभावकों के पास पहुंच जाये, जैसे कि - शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर झा का पूर्ण विवरण दिया जाता है, समय समय पर समाचार पत्रों में विज्ञापन दिये जाते हैं, रेडियो जिगल के द्वारा तथा हेल्पलाइन न. के द्वारा भी प्रचार किया जाता है।																
(च) सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिए स्कूलों पर कितना व्यय किया जा रहा है, और	दिल्ली सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने के लिये विगत वर्षों में निजी स्कूलों पर व्यय का विवरण निम्नलिखित है - <table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th> <th>व्यय (रु लाखों में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2011-12</td> <td>161.39</td> </tr> <tr> <td>2012-13</td> <td>422.28</td> </tr> <tr> <td>2013-14</td> <td>1174.80</td> </tr> <tr> <td>2014-15</td> <td>2458.00</td> </tr> <tr> <td>2015-16</td> <td>3447.33</td> </tr> <tr> <td>2016-17</td> <td>3686.37</td> </tr> <tr> <td>2017-18</td> <td>5827.06</td> </tr> </tbody> </table>	वर्ष	व्यय (रु लाखों में)	2011-12	161.39	2012-13	422.28	2013-14	1174.80	2014-15	2458.00	2015-16	3447.33	2016-17	3686.37	2017-18	5827.06
वर्ष	व्यय (रु लाखों में)																
2011-12	161.39																
2012-13	422.28																
2013-14	1174.80																
2014-15	2458.00																
2015-16	3447.33																
2016-17	3686.37																
2017-18	5827.06																
(छ) प्राइवेट स्कूल प्रबंधन की इसमें क्या भूमिका है?	मान्यता प्राप्त निजी स्कूल शिक्षा निदेशालय के नियमानुसार आवंटित ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार को दाखिला देना।																


 DBE (PGMS)
 Dir. of Education
 Govt. of NCT of Delhi